अमर उजाला

प्रवाह

नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 9 मई 2019

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे अपने विवादों का समाधान शब्दों से करें, हथियारों से नहीं।

-बिल क्लिंटन

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

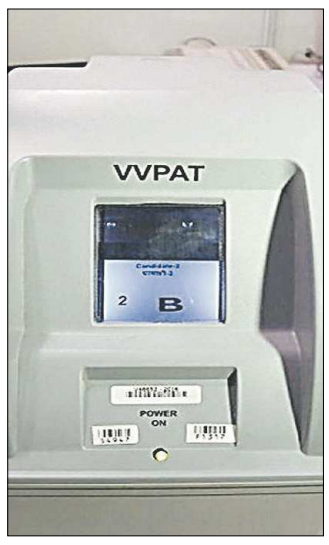

विपक्ष दो फीसदी से अधिक ईवीएम के वीवीपैट से मिलान को पारदर्शिता की लड़ाई बता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मांग खारिज हो जाने के बाद उसे इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने से बचना चाहिए।

वीवीपैट और विपक्ष

पचास फीसदी ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराने से संबंधित विपक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को कानूनी रूप से तो खत्म कर दिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा खत्म नहीं होने वाला। दरअसल शीर्ष अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विगत आठ अप्रैल को अपने फैसले में विधानसभा के पांच बूथों पर ईवीएम के वीवीपैट से औचक मिलान करने का आदेश दिया था। उसी दौरान कुल 21 विपक्षी दलों ने पचास फीसदी ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि विपक्ष की यह मांग व्यावहारिक नहीं थी, क्योंकि पचास फीसदी ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने पर ईवीएम से वोटिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हालांकि सुनवाई के दौरान विपक्षी दल 33 या 25 फीसदी ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने पर भी राजी थे। जबकि इसमें भी काफी समय लगता, जिससे नतीजे में देरी होती। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अगर मुट्ठी भर लोग भी संदेह कर रहे हों, तो उसके निराकरण की कोशिश होनी चाहिए। फिर यह मांग विपक्ष के 21 राजनीतिक दलों ने की, जिनमें कुछ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। आखिर पारदर्शिता की खातिर ही चुनाव आयोग ने इस चुनाव से हर बूथ पर वीवीपैट का प्रावधान किया है। अगर 25 फीसदी ईवीएम का वीवीपैट से मिलाना करना अव्यावहारिक है, तो कम से कम 10 फीसदी के मिलान पर तो विचार किया ही जा सकता है, जबकि अभी यह महज दो फीसदी ही है, जिसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बेशक ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को अभी तक साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग गलत नहीं है। यह अच्छा है कि चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में विपक्ष की चिंताओं से सहमति जताई है। चूंकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बहाल करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि आयोग और विपक्ष सहमति के बिंदु तक पहुंचें। विपक्ष द्वारा पारदर्शिता की लड़ाई जारी रखने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ईवीएम पर चुनाव आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के रुख के बाद उसे इस मुद्दे को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाने से बचना चाहिए।

वादों और मुद्दों के बीच

दबे कुचले वर्ग की आवाज, अगड़ी जातियों की तरह प्रबल भले न हो, लेकिन वोट उनका आसरा है। वह फिर से कमल का बटन दबाएंगे या गठबंधन की तरफ आकर्षित हैं, इस पूरी राजनीतिक चर्चा को सूक्ष्मता से समझना होगा

मनीषा प्रियम, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

लोकसभा चुनाव-2019 में कैसी है 'पुरबिया बयार'? लोकसभा चुनाव में वाराणसी और पूर्वांचल से सटे इलाकों व उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों शहरों में इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्या इस बार भी 2014 की तरह कोई राजनीतिक बयार चल रही है। कुछ नए प्रस्तावित मुद्दे, जैसे कि, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जनमत एकाग्रचित्त हो चला है, या कहीं केवल जातिगत समीकरण स्थानीय रूप धारण कर राजनीति की चर्चा पर पर्दा डाल रहे हैं।

सबसे पहले बात करते हैं, बनारस की। यहां कई वादे किए गए, कि यह शहर क्योटो जैसा बन जाएगा, स्वच्छता का मॉडल बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद होने के नाते सीधा संवाद होगा और नौजवानों की आकांक्षाओं को पर लगेंगे। शहर में हर कोई कहता है कि यहां से तो मोदी ही जीतेंगे। मुद्दों पर बहस करें, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, जो कहते हैं कि कुछ खास काम नहीं हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्साह का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महामना मदन मोहन मालवीय के नाम और परिवार का उचित सम्मान किया है। लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से चर्चा करने पर वे दबी जुबान से बताते हैं कि उन पर काफी अंकुश लगा है।

बिहार के सीवान जिले के सुनील पासवान बीएचयू में भूगोल के छात्र थे और परास्नातक के बाद उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली। लेकिन उनके लिए आगे के दरवाजे बंद होने लगे, क्योंकि पीएचडी में सीटें कम कर दी गईं। उनका मानना है कि जिनकी पहुंच है और जो प्रोफेसरों को पहचानते हैं, वही यहां से आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे तमाम छात्र हैं, जो यहां से पढ़कर समाज में कुशल पेशेवर बनना चाहते हैं। लेकिन इनके मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है, और किसी मुद्दे को वे उठाना चाहें, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का भय रहता है। स्पष्ट है कि नौजवानों की आकांक्षाओं और रोजगार की चर्चा करते हुए 2014 की जो 'पुरबिया बयार' बनी थी, उन पर संवाद की संभावना अब नहीं है।

भदैनी की ओर जाने वाली सड़क पर रस्सी और दातून बेचने वाले दुकानदार से जब सफाई व्यवस्था पर बात की तो उसने कहा, 'खुदै जाके अंदर गलियन में देख ला।' अस्सी घाट पर सड़क पर सार्वजनिक शौचालय, प्रवासी भारतीय दिवस की होर्डिंग्स के पीछे छिपा दिए गए हैं। नए अच्छे सार्वजनिक शौचालय दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, पर गंगाजल का रंग काईनुमा हरा दिखाई देता है। गंगा घाटों के किनारे प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, हालांकि दशाश्वमेघ घाट पर शाम की गंगा आरती में रौनक दिखती है।

नाविक गोपाल मांझी बताते हैं, कि विदेश से लाया गया एक लग्जरी बजरा भी अब बनारस की गंगा में चलता है! नाव में बैठे एक बंधु कहते हैं, कि गरीबी उन्मूलन हो न हो, बनारस में अब अमीरी प्रबंधन पर विशेष बल है। लंका से गोदौलिया पहुंचें, और काशी विश्वनाथ के दर्शन को घुसते ही नई प्रबंधन व्यवस्था दिखाई देती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ढहाए गए पड़ोसी मंदिरों के मलबों की सफाई की जा रही है। कुछ लोग बताते हैं कि इर्द-गिर्द के अतिक्रमण को दूर करने के लिए इनको ढहाना आवश्यक था। पंद्रहवीं सदी के आसपास बनी कई इमारतें अब ढहाई जा चुकी हैं। अयोध्या से पहले काशी विश्वनाथ में एक भव्य मंदिर का अब बन जाना लगभग तय है।

शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर पता चलता है कि वहां रोजगार, गांवों के सौंदर्यीकरण की कोई चर्चा नहीं हो रही है। लखनऊ से बनारस के रास्ते में अमेठी के कमालगंज ब्लॉक में एक हेलीकॉप्टर के उतरने की तैयारी हो रही थी। पूछने पर पता चला कि हार्दिक पटेल यहां एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। गांव में बातचीत के दरम्यान यह दिखा कि यहां की पटेल बिरादरी हार्दिक को सुनने के लिए इकट्ठा है। गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश की पटेल जाति दोनों आर्थिक पायदान के दो सिरे पर हैं, सामाजिक तौर से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन पटेल सरनेम के आधार पर शायद किसी तरह अखिल भारतीय राजनीतिक संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सभा में अल्पसंख्यक व दलित दोनों मौजूद हैं। चर्चा किसानी के मुद्दों पर है। हार्दिक की बात लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन उनके मुद्दे हार्दिक के भाषण से भिन्न हैं। प्रेम कली कहती हैं कि रहने को छत नहीं हैं, छप्पर के नीचे खाना बनाती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा मुद्दा गरीबी है।

कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दल जमीनी मुद्दों से कतरा रहे हैं और शब्दों की लड़ाई में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर मुद्दों में समानता है। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के जबरौली गांव में महिलाएं बताती हैं कि उज्जवला योजना में सिलेंडर मिला था, लेकिन अब यह भरा नहीं जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मौर्य समुदाय के वोट भाजपा को जाएंगे। दबी जुबान से कई लोग कहते हैं कि भाजपा उनकी मजबूरी बन गई है। बताते हैं कि दो हजार रुपये तो मिले हैं, लेकिन किसानी ठप हो जाने के घाटे की पूर्ति इससे नहीं हो सकती। दलित मतदाताओं का 2014 में भाजपा की तरफ झुकाव कुछ मत्वपूर्ण वादों पर था, लेकिन महंगाई पर अब कोई चर्चा नहीं करता, जबकि रोजगार के मुद्दे पर निराशा छाई हुई है।

इस पूरे माहौल में लहर जैसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बक्सी का तालाब, मलिहाबाद इन सभी इलाकों में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा पुरजोर है। वोटिंग भले ही जातिगत समीकरणों पर हो, लेकिन निराशा का कारण यह है कि लोकहित के लिए किए गए अनेक वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। और वर्तमान परिस्थिति की दिक्कतों के लिए कल्याणकारी योजनाएं काफी नहीं दिख रहीं। दबे कुचले वर्ग की आवाज, अगड़ी जातियों की तरह प्रबल भले न हो, लेकिन वोट उनका आसरा है। इस चर्चा के बीच वह फिर से कमल का बटन दबाएंगे या गठबंधन की तरफ आकर्षित हैं, इस पूरी राजनीतिक चर्चा को सूक्ष्मता से समझना होगा, बहरहाल निर्णायक तर्क तो अब 23 मई के बाद निकलेंगे।

अंतर्ध्वनि

>>गजानन माधव मुक्तिबोध

पुरानी परंपरा छूटती नहीं है, पर वह परंपरा है मेरी ही

मेरी कविताओं के प्रांत-परिवर्तन का कारण है, आंतरिक जिज्ञासा। परंतु इस जिज्ञासु-वृत्ति का वास्तव (ऑब्जेक्टिव) रूप अभी तक कला में नहीं पा सका हूं। वह उपन्यास द्वारा ही प्राप्त हो सकेगा। वैसे काव्य में जीवन के चित्र की—यथा वैज्ञानिक 'टाइप' की—उद्भावन की, अथवा शुद्ध शब्द-चित्रात्मक कविता हो सकती है। इन्हीं के प्रयोग मैं करना चाहता हूं। पुरानी परंपरा बिलकुल छूटती नहीं है, पर वह परंपरा है मेरी ही और उस का प्रसार अवश्य होना चाहिए। जीवन के इस वैविध्यमय विकास-स्रोत को देखने के लिए इन भिन्न-भिन्न काव्य-रूपों को, यहां तक की नाट्य-तत्त्व को, कविता में स्थान देने की आवश्यकता है। पिछले बीस वर्षों में न मालूम कितनी बातें घटित हुई हैं। वे सबके सामने हैं। मेरी अपनी जिंदगी जिन तंग गलियों में चक्कर काटती रही, उन्हें देखते हुए यही मानना पड़ता है कि साधारण श्रेणी में रहने वाले हम लोगों को अस्तित्व-संघर्ष के प्रयासों में ही समाप्त होना है। मेरा अपना प्रदीर्घ अनुभव बताता है कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की वास्तविक स्थिति केवल उनके लिए है, जो उस स्वातन्त्र्य का प्रयोग करने के लिए सुपुष्ट आर्थिक अधिकार रखते हों, जिससे कि वे परिवार सहित मानवोचित जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का ऐसा प्रयोग भी कर सकें जो विवेकपूर्ण हो। और लक्ष्योन्मुख हो अपने जीवन के आर्थिक आधार को दृढ़ और सुपुष्ट करने के लिए व्यक्ति के व्यवसायीकरण का मार्ग भी सामने आता है। मेरे लेखे यह अत्यंत अनुचित मार्ग है। और कम से कम मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया; लेकिन वह मार्ग तो सामने आता ही है और व्यवसायीकरण-व्यापारीकरण का दबाव तो तीव्रतर होता जाता है। सच तो यह है कि व्यक्ति की सच्ची आत्मपरीक्षा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा, सबसे प्रधान समय, उस इम्तिहान का सबसे नाजुक दौर यही आज का युग है।

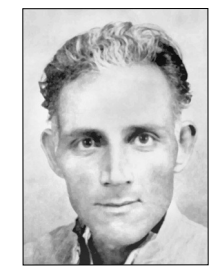

मंजिलें और भी हैं

>> सुमेधा कुशवाहा

तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती हूं

मैंने आईटीएस डेंटल कॉलेज से बीडीएस और फिर एमडीएस की डिग्री ली। मैं एक डेंटिस्ट हूं और तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती हूं। डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान मैंने कैंसर की भयावहता और देश में इसके व्यापक प्रसार के बारे में जाना। हमें उस दौरान यह भी बताया गया कि कैंसर के बढ़ते आंकड़े की वजह तंबाकू का बढ़ता चलन है। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे भी तंबाकू का सेवन करते हैं, जिस कारण उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनमें से अनेक में कैंसर के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। दरअसल डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज करिकुलम के तहत हमें गांवों में लगाए गए मेडिकल कैंपों में काम करना पड़ता था। तब हमें महसूस होता था कि जो गांव छूट गए हैं, वहां भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि दूर स्थित उन गांवों के लोग कैंपों में नहीं आ सकते थे।

उस दौरान हमारे पुरुष साथी जब कैंपों में ग्रामीणों का इलाज करते थे, तब मैं उन गांवों में तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाती थी। चूंकि मैं तंबाकू के खिलाफ एक मिशन के तहत काम करना चाहती थी, इसलिए अगस्त, 2014 में मैंने अपने कुछ डॉक्टर साथियों के साथ एटीटीएसी नाम से एक संस्था का गठन किया। यह जरूरी था, क्योंकि अलग से संस्था बनने पर ही हम इस लक्ष्य के तहत समर्पित होकर काम कर सकते थे। इसके अलावा समय की कमी भी एक मुद्दा थी। अब मैं और हमारे साथी अस्पताल की टाइमिंग से पहले और बाद में अपनी संस्था के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह अवकाश का पूरा दिन मैं संस्था के लिए काम करती हूं। हमारी संस्था को फंडिंग युवराज सिंह फाउंडेशन से होती है। लेकिन फंडिंग बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संस्था में सिर्फ एक ही वेतनभोगी कर्मचारी है, बाकी लोग इसमें पार्ट टाइम काम करते हैं। हमारी संस्था के पांच लक्ष्य हैं-जागरूकता फैलाना, तंबाकू की आदत छुड़ाना, तंबाकू का अत्यधिक इस्तेमाल करने वालों को सचेत करना, रणनीति बनाना और मदद करना तथा फोलो अप, जिसके तहत यह जाना जाता है कि इन उपायों का प्रभावित लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

अभी तक मेरे प्रयास से तीस हजार लोग तंबाकू छोड़ चुके हैं। मैं उन्हें तंबाकू छोड़ने का लाभ बताती हूं।

अपने अभियान के तहत मैं अनेक ऐसे बच्चों और युवाओं के संपर्क में आई, तंबाकू के नियमित सेवन के कारण जिनका बुरा हाल था। एक युवा का इलाज करते हुए मुझे पता चला कि वह छह साल की उम्र से तंबाकू का सेवन कर रहा था। ऐसे ही एक कैंप में तेरह साल के एक लड़के को मुंह का कैंसर था और वह अपना मुंह तक नहीं खोल पाता था। उसकी हालत देखकर मुझे रोना आ जाता था। मेरे पति, जो खुद एक डॉक्टर हैं, चेन स्मोकर थे और रोज तीस सिगरेट पीते थे। पर मेरी लगातार कोशिशों से उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया। अभी तक मैंने करीब तीस हजार लोगों की, जिनमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, तंबाकू छुड़ाई है। पर ऐसे भी मामले हैं, जिनमें कुछ दिनों के परहेज के बाद लोगों ने फिर से तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया। शुरुआत में ऐसे मामलों में बहुत गुस्सा आता था, पर अब ऐसे मामलों में भी शांत रहने की आदत पड़ चुकी है। मैं अपनी संस्था की तरफ से कॉरपोरेट ऑफिसों में भी बुलाए जाने पर जाती हूं और लोगों को तंबाक का इस्तेमाल छोड़ने के लिए कहती हूं। लोगों को यह समझाया जाता है कि जितनी जल्दी वे तंबाकू का सेवन छोड़ेंगे, उतना लाभ होगा। मैंने देखा है कि देर हो जाने पर स्थिति बिगड़ जाती है।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

डिजिटल भारत में रोजगार

इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ने से पारंपरिक विपणन माध्यम अपनी चमक खो रहे हैं। अधिकांश समय लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इसलिए विक्रेताओं का इस माध्यम के जरिये उनके साथ जुड़ना सही भी है।

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'डिजिटल इंडियाः टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म ए कनेक्टेड नेशन' में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि भारत डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या करीब 56 करोड़ हो गई है और इस परिप्रेक्ष्य में दुनिया में वह अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ चुका है। वर्ष 2018 में भारत के स्मार्टफोन धारकों ने 12.3 अरब ऐप डाउनलोड किए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इंटरनेट डाटा की लागत वर्ष 2013 के बाद से 95 फीसदी कम हो चुकी है, जबकि फिक्स्ड लाइन पर डाउनलोड की रफ्तार चौगुनी हो चुकी है।

इसके कारण प्रति व्यक्ति मोबाइल डाटा उपभोग सालाना 152 फीसदी बढ़ चुका है। खासतौर से आधार, जियो, जनधन और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण भारत तेजी से डिजिटल हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद 1.03 करोड़ औद्योगिक एवं कारोबारी इकाइयां कर-भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रही हैं। छोटे गांवों में रहने वाले बेहद सामान्य लोग भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर खबरें देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, पैसों का लेनदेन करते हैं और खरीदारी करते हैं।

मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025 तक छह से साढ़े छह करोड़ रोजगार अवसर पैदा होंगे, वहीं इसकी वजह से संकट में आई करीब चार से साढ़े चार करोड़ परंपरागत नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन डिजिटलीकरण से करीब दो करोड़ से अधिक नई नौकरियां निर्मित होंगी। इसमें कोई दोमत नहीं कि दुनिया भर में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कई क्षेत्रों में रोजगार तेजी से खत्म हो रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां रोजगार की भरमार आने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा ही क्षेत्र है, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन तथा गेम कंसोल जैसे डिजिटल माध्यम के जरिये विभिन्न उत्पादों के प्रचार से है।

इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ने से पारंपरिक विपणन माध्यम अपनी चमक खो रहे हैं। अधिकांश समय लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इसलिए विक्रेताओं का इस माध्यम के जरिये उनके साथ जुड़ना सही भी है। डिजिटल मार्केटिंग का खर्च वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। व्यापारी इस बात को भलीभांति समझने लगे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए कितनी लाभप्रद है। गौरतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग उत्पाद को जारी करने, प्रचार, बिक्रीय ब्रांड छवि बनाना, जन संपर्क या उपभोक्ता सेवा जैसी अपेक्षा रखने वाली कंपनियों के लिए उपयोगी है। इसके लचीलेपन, सहुलियत और किफायती दर में उपलब्ध होने से यह बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसकी नई, आकर्षक और रचनात्मक विशेषताएं कंपनियों को वर्तमान उपभोक्ताओं तक पहुंचने और नए बाजार तलाशने में मदद करती हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस अनूठी तकनीक को नहीं अपनाने पर कंपनियों को कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मैकेंजी ग्लोबल की इस रिपोर्ट का यह संदेश एकदम साफ है कि डिजिटलीकरण की संभावनाएं अगर अपरिहार्य नहीं, तो इतनी अधिक लाभप्रद हैं कि इस नई हकीकत के मुताबिक हर क्षेत्र में प्रगति करने और हर क्षेत्र में अच्छे रोजगार के लिए डिजिटल की दुनिया को अपनाना होगा। जो कोई ऐसा नहीं करेगा, वह पीछे छूट जाएगा। नई पीढ़ी को जहां खुद को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार होना है, वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुराइयों से उद्योग-कारोबार और उपभोक्ताओं को बचाने की रणनीतिक पहल भी जरूरी है।

खुली खिड़की

वैश्विक समुद्री सीमाएं

दुनिया के विभिन्न देशों के साथ उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के उद्देश्य से 1982 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी (यूएनसीएलओएस) कहा जाता है। इन देशों में सबसे लंबी समुद्री सीमा कनाडा की है।

नोट : आंकड़े किलोमीटर में हैं।

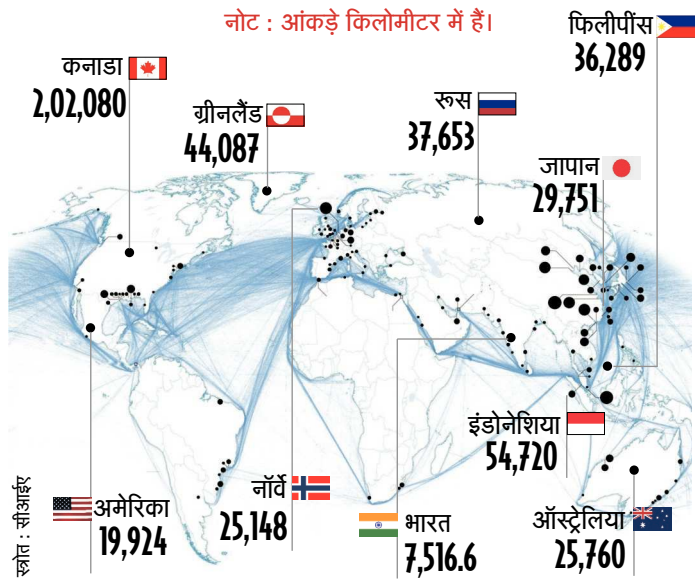

स्रोत : सीआईए

संत की विनम्रता

सत्संग

ब्रह्मनिष्ठ संत स्वामी दयानंद गिरि शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे। वह अक्सर कहा करते थे कि धर्मशास्त्रों का सार यही है कि मनुष्य हर प्रकार के अभिमान से दूर रहकर सदैव विनम्रता का व्यवहार करे। एक बार स्वामी जी राजस्थान पहुंचे। श्रीनाथजी के दर्शन के बाद वह भोजन प्राप्त करने मंदिर के भंडारे में पहुंचे। वहां भोजनालय का प्रबंधक किसी से कह रहा था, आज बर्तन साफ करने वाला कर्मचारी नहीं आ पाया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्वामीजी ने जैसे ही यह सुना, वह जूठे बर्तन साफ करने में जुट गए। भंडारे का व्यवस्थापक और अन्य संतगण उनकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। उसी शाम मंदिर के सभागार में विद्वानों के बीच संस्कृत में शास्त्र चर्चा का आयोजन था, इसमें अनेक संत और भाग ले रहे थे। स्वामी दयानंद गिरि एक कोने में जा बैठे। उन्होंने चर्चा के बीच में खड़े होकर विनयपूर्वक कहा, आप लोग प्रश्न का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शुद्ध उच्चारण भी बता दिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने देखा कि यह तो वहीं संत है, जो थोड़ी देर पहले जूठे बरतन साफ कर रहा था। वह हतप्रभ रह गया। जब उसे पता चला कि वह स्वामी दयानंद गिरि जी हैं, तो वह उनसे क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने कहा, साधु के लिए कोई भी काम बड़ा-छोटा नहीं होता। उसे तो हमेशा सेवा करने को तत्पर रहा चाहिए।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

आदिल, पिता और फुटबॉल

एक लड़के की कहानी, फुटबॉल में जिसके हुनर को उसके पिता ने ही पहचाना।

आदिल पांचवीं कक्षा में था, जब उसके पिता रईस ने उसे फुटबॉल लाकर दी। आदिल को फुटबॉल खेलने में खूब मजा आने लगा। धीरे-धीरे स्टेट टीम के कोच ने आदिल को स्पोर्ट्स अकादमी में शामिल कर लिया। रईस रोज आदिल को समय पर अकादमी लेकर आता था। आदिल को तैयारी करते हुए करीब पांच साल बीत गए। पर उसे कभी टीम में खेलने का मौका नहीं मिल पाया। वह अंतिम खिलाड़ियों में ही रह जाता था। हर बार रईस के पूछने पर आदिल चुप्पी साध जाता था। रईस समझ जाता था कि आदिल को खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी बेटे का मनोबल बनाए रखने के लिए वह कहता था, मुझे यकीन है कि जिस दिन तुम खेलोगे, पूरा स्टेडियम तुम्हारा फैन हो जाएगा। पर दुर्भाग्य से एक दिन घर लौटते वक्त रईस की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कोच ने आदिल को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। पर वह दूसरे ही दिन स्टेडियम पहुंच गया। उस दिन दूसरे राज्य की टीम से मैच था और आदिल की टीम हार रही थी। आदिल ने कोच से खेलने के लिए दरख्वास्त की। कोच जानता था कि टीम हार जाएगी, क्योंकि दूसरी टीम दो गोल से आगे थी। कोच ने आदिल को उतार दिया। साथी खिलाड़ी आदिल को देख भौंचक्के थे। पर उसके आते ही मैच पलटने लगा। आदिल को कोई रोक नहीं पा रहा था और बॉल इधर से उधर रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी। खेल खत्म हुआ, तो आदिल की टीम 3-2 से मैच जीत गई थी। साथियों ने आदिल को कंधों पर उठाकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया। जश्न के बाद कोच ने चेंजरूम में जाकर देखा कि आदिल रो रहा था। कोच ने कहा, आज तो तुमने जादू कर दिया। काश, तुम्हारे पिता तुम्हें देख पाते। आदिल ने कहा, सर, मेरे पिता नेत्रहीन थे। पर आज पहली बार उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा होगा।

सपने वे भी देखते हैं, जिनकी आंखें नहीं होतीं।